Journal of Advances in Science and Technology
Vol. 16, Issue No. 1, March-2019, ISSN 2230-9659

महिलाओं की रोजगार के लिए राष्ट्रीय नीति

Priti Deshlahara[1]* Dr. Deepa Chaudhary[2]

[1] Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajastan

[2] Associate Professor, OPJS University, Churu, Rajastan

सार – 2001 में अपनाई गई महिलाओं के सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय नीति में कहा गया है कि "महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार, शारीरिक और मानसिक, चाहे वे घरेलू या सामाजिक स्तर पर हों, जिनमें रीति-रिवाजों, परंपराओं या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले लोगों से प्रभावी ढंग से निपटा जाएगा। इसकी घटनाओं को खत्म करना। ऐसी हिंसा की रोकथाम के लिए संस्थानों और तंत्र / योजनाएं बनाई जाएंगी और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा, जिसमें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी प्रथाएं शामिल हैं, हिंसा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए और अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए। इस तरह की हिंसा। महिलाओं और लड़कियों की तस्करी से निपटने के लिए प्रोग्रामरों और उपायों पर एक विशेष जोर दिया जाएगा।"

संचालन रणनीतियों के तहत, नीति प्रदान करती है:

क) प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों का सख्त प्रवर्तन और हिंसा और लिंग संबंधी अत्याचारों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिकायतों का त्वरित निवारण;

ख) संगठित / असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के कार्य स्थल पर संरक्षण और यौन उत्पीड़न को रोकने और दंडित करने के उपाय

ग) महिलाओं के खिलाफ अपराध - उनकी घटनाओं, रोकथाम, जांच, जांच और अभियोजन की समीक्षा नियमित रूप से केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर सभी अपराध समीक्षा में की जानी चाहिए।

----------♦----------

परिचय:

भारतीय संविधान में लैंगिक समानता का सिद्धांत अपने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में निहित है। संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का भी अधिकार देता है।

एक लोकतांत्रिक राजनीति के ढांचे के भीतर, हमारे कानूनों, विकास नीतियों, योजनाओं और प्रोग्रामरों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-78) के बाद से महिलाओं के मुद्दों पर कल्याण से विकास तक के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया है। हाल के वर्षों में महिलाओं की स्थिति के निर्धारण में महिलाओं के सशक्तीकरण को केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है। महिलाओं के अधिकारों और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन (1993) में महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं।

1.1 भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानव अधिकारों के उपकरणों की पुष्टि की है। उनमें से प्रमुख है 1993 में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन (CEDAW)।

1.2 द मेक्सिको प्लान ऑफ एक्शन (1975), नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज़ (1985), बीजिंग घोषणा और साथ ही प्लेटफ़ॉर्म फॉर एक्शन (1995) और

www.ignited.in

UNGA सत्र द्वारा लिंग समानता और विकास और विकास के लिए अपनाए गए आउटकम दस्तावेज़। 21 वीं सदी, जिसका शीर्षक है "बीजिंग कार्रवाई और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई और पहल", भारत द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए अनारक्षित रूप से समर्थन किया गया है।

1.3 यह नीति नौवीं पंचवर्षीय योजना और महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य सेक्टोरल नीतियों की प्रतिबद्धताओं पर भी ध्यान देती है।

1.4 महिलाओं की आवाजाही और गैर-सरकारी संगठनों का एक विस्तृत प्रसार नेटवर्क जिसमें महिलाओं की चिंताओं के बारे में प्रेरणादायक पहलों में महिलाओं की चिंताओं के बारे में मजबूत जमीनी उपस्थिति और गहरी अंतर्दृष्टि है।

1.5 हालांकि, संविधान में वर्णित लक्ष्यों, कानून, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, और एक तरफ संबंधित तंत्र और भारत में महिलाओं की स्थिति की स्थितिजन्य वास्तविकता के बीच व्यापक अंतर मौजूद है। भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति की रिपोर्ट में इसका व्यापक विश्लेषण किया गया है, "टूवर्ड इक्वलिटी", 1974 और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन, 1988-2000, श्रमशक्ति रिपोर्ट, 1988 और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन में प्रकाश डाला गया।

लक्ष्य और उद्देश्य

इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण लाना है। नीति को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाएगा ताकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। विशेष रूप से, इस नीति के उद्देश्यों में शामिल हैं

(i) महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों के माध्यम से एक वातावरण तैयार करना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकें

(ii) सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान आधार पर महिलाओं द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का डी-ज्यूर और डी-फैक्टो आनंद - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक

(iii) राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुंच

(iv) महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, रोजगार, समान पारिश्रमिक, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यालय आदि के लिए समान पहुँच।

पॉलिसी के नुस्खे:

न्यायिक कानूनी प्रणाली

कानूनी-न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और लिंग के प्रति संवेदनशील बनाया जाएगा, खासकर घरेलू हिंसा और व्यक्तिगत हमले के मामलों में। नए कानून बनाए जाएंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा की जाएगी कि न्याय जल्दी हो और अपराधियों को दी गई सजा अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो

निर्णय लेना

निर्णय लेने में शक्ति साझाकरण और सक्रिय भागीदारी में महिलाओं की समानता, सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेने सहित सशक्तीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किया जाएगा। विधायी, कार्यकारी, न्यायिक, कॉर्पोरेट, वैधानिक निकायों सहित हर स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की समान पहुंच और पूर्ण भागीदारी की गारंटी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे, साथ ही सलाहकार आयोग, समितियां, बोर्ड, ट्रस्ट आदि: सकारात्मक कार्रवाई। उच्च विधायी निकायों सहित आरक्षण / कोटा, जब भी समयबद्ध आधार पर आवश्यक हो, पर विचार किया जाएगा। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के अनुकूल कार्मिक नीतियों को भी तैयार किया जाएगा।

विकास प्रक्रिया में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्यधारा बनाना

सभी विकास प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, प्रतिभागी और प्राप्तकर्ता के रूप में महिलाओं के दृष्टिकोण की मुख्यधारा सुनिश्चित करने के लिए 4.1 नीतियां, कार्यक्रम और प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। नीतियों और कार्यक्रमों में जहां कहीं भी अंतराल है, वहां इन पर काबू पाने के लिए महिलाओं के विशिष्ट हस्तक्षेप किए

www.ignited.in

जाएंगे। इस तरह के मुख्यधारा तंत्र की प्रगति का समय-समय पर आकलन करने के लिए समन्वय और निगरानी तंत्र भी तैयार किया जाएगा। परिणामस्वरूप महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं को सभी संबंधित कानूनों, क्षेत्रीय नीतियों, योजनाओं और कार्रवाई के प्रोग्रामर में विशेष रूप से संबोधित और प्रतिबिंबित किया जाएगा।

गरीबी उन्मूलन

चूंकि महिलाओं में गरीबी रेखा से नीचे की अधिकांश आबादी शामिल है और वे अक्सर अत्यधिक गरीबी की स्थितियों में रहती हैं, इसलिए इंट्रा-हाउस और सामाजिक भेदभाव की कठोर वास्तविकताओं को देखते हुए, मैक्रो आर्थिक नीतियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विशेष रूप से जरूरतों और समस्याओं को संबोधित करेंगे ऐसी महिलाएं। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार किया जाएगा जो पहले से ही महिलाओं के लिए विशेष लक्ष्यों के साथ उन्मुख हैं। गरीब महिलाओं को संगठित करने और सेवाओं के अभिसरण के लिए कदम उठाए जाएंगे, उन्हें आर्थिक और सामाजिक विकल्पों की एक श्रृंखला पेश करके, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आवश्यक समर्थन उपायों के साथ।

माइक्रो क्रेडिट

उपभोग और उत्पादन के लिए महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए, नए की स्थापना, और मौजूदा माइक्रो-क्रेडिट तंत्र और सूक्ष्म-वित्त संस्थान को मजबूत करने के लिए किया जाएगा ताकि ऋण की पहुंच बढ़े। मौजूदा वित्तीय संस्थानों और बैंकों के माध्यम से ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहायक उपाय किए जाएंगे, ताकि गरीबी रेखा से नीचे की सभी महिलाओं को ऋण की आसान पहुंच हो।

महिला और अर्थव्यवस्था

महिलाओं के दृष्टिकोण को ऐसी प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को संस्थागत बनाकर वृहद आर्थिक और सामाजिक नीतियों को डिजाइन करने और लागू करने में शामिल किया जाएगा। उत्पादकों और श्रमिकों के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों (घर आधारित श्रमिकों सहित) में मान्यता दी जाएगी और रोजगार से संबंधित उचित नीतियां और उनके कामकाज की स्थिति तैयार की जाएगी। इस तरह के उपायों में शामिल हो सकते हैं:

जहां भी आवश्यक हो, काम की पारंपरिक अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या और पुनर्वितरण। जनगणना के रिकॉर्ड में, उत्पादकों और श्रमिकों के रूप में महिलाओं के योगदान को प्रतिबिंबित करना।

भूमंडलीकरण ने महिलाओं की समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई चुनौतियां पेश की हैं, जिनके लिंग प्रभाव का पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों से जो महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कमीशन किया गया था, यह स्पष्ट है कि रोजगार और रोजगार की गुणवत्ता के लिए नीतियों को फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभों को असमान रूप से व्यापक आर्थिक विषमताओं के लिए वितरित किया गया है, गरीबी का स्त्रैणकरण, बढ़ती लैंगिक असमानता के कारण अक्सर काम करने की स्थिति बिगड़ती है और विशेष रूप से अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में असुरक्षित कामकाजी वातावरण। रणनीतियाँ महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने और उन्हें नकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जो वैश्विक प्रक्रिया से प्रवाहित हो सकते हैं.

महिला और कृषि

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, उत्पादकों के रूप में, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाएंगे कि प्रशिक्षण, विस्तार और विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उनकी संख्या के अनुपात में उन तक पहुंचे। कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से संबद्ध अन्य व्यवसायों जैसे बागवानी, पशुधन सहित छोटे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा।

महिला और उद्योग

इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग और वस्त्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका इन क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है। उन्हें विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भाग लेने के लिए श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सहायता सेवाओं के संदर्भ में व्यापक समर्थन दिया जाएगा।

समर्थन सेवाएं

महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं का प्रावधान, बच्चों की देखभाल की सुविधाओं की तरह, कार्य स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में वृद्धों के लिए, विकलांगों के लिए घर और विकलांगों का विस्तार किया जाएगा और एक सक्षम वातावरण बनाने और सामाजिक, राजनीतिक में उनके पूर्ण सहयोग को सुनिश्चित

www.ignited.in

करने के लिए सुधार किया जाएगा। और आर्थिक जीवन। महिलाओं को विकास प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं के अनुकूल कार्मिक नीतियों को भी तैयार किया जाएगा।

स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें पोषण और स्वास्थ्य दोनों सेवाएं शामिल हैं, को अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी चरणों में महिलाओं और लड़की की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, प्राथमिकता की चिंता है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के लिए राष्ट्रीय जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को दोहराती है। महिलाओं को व्यापक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। उन उपायों को अपनाया जाएगा जो महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन्हें सूचित विकल्पों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, यौन और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति उनकी भेद्यता जैसे कि मलेरिया, टीबी, और जल जनित बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, के साथ-साथ उच्च रक्तचाप के कारण। और कार्डियो-पल्मोनरी रोग। एचआईवी / एड्स और अन्य यौन संचारित रोगों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों को लैंगिक दृष्टिकोण से निपटाया जाएगा।

शिशु और मातृ मृत्यु दर की समस्याओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, और शीघ्र विवाह से मृत्यु, जन्म और विवाह पर सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा।

पोषण

कुपोषण और बीमारी के उच्च जोखिम के मद्देनजर जो कि तीनों महत्वपूर्ण अवस्थाओं में महिलाओं का सामना करते हैं, शैशवावस्था और बचपन, किशोर और प्रजनन चरण, जीवन के सभी चरणों में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा। चक्र। यह भी किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण लिंक को देखते हुए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के बीच मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे क्योंकि यह विभिन्न बीमारियों और अक्षमताओं की ओर जाता है।

पेयजल और स्वच्छता

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज निपटान, शौचालय की सुविधा और घरों की सुलभता के भीतर स्वच्छता की व्यवस्था में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी सेवाओं के नियोजन, वितरण और रखरखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास और आश्रय

महिलाओं के दृष्टिकोण को आवास नीतियों, आवास कॉलोनियों की योजना और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आश्रय का प्रावधान शामिल किया जाएगा। एकल महिलाओं, घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, छात्रों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुओं सहित महिलाओं के लिए पर्याप्त और सुरक्षित आवास और आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वातावरण

महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनके दृष्टिकोण पर्यावरण, संरक्षण और बहाली के लिए नीतियों और कार्यक्रमों में परिलक्षित होंगे। अपनी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के संरक्षण और पर्यावरण क्षरण के नियंत्रण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश हिस्सा अभी भी ऊर्जा के स्थानीय रूप से उपलब्ध गैर-वाणिज्यिक स्रोतों जैसे कि पशु गोबर, फसल अपशिष्ट और ईंधन लकड़ी पर निर्भर करता है। पर्यावरण अनुकूल तरीके से इन ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, नीति का लक्ष्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा।

विज्ञान और तकनीक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए 6.11 कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा। इनमें उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए प्रेरित करने के उपाय शामिल होंगे और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी आदानों के साथ विकास परियोजनाएं पूरी तरह से महिलाओं को शामिल करें। वैज्ञानिक स्वभाव और जागरूकता विकसित करने के प्रयासों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। उन क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष

www.ignited.in

उपाय किए जाएंगे जहां उनके पास संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विशेष कौशल हैं। महिलाओं की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने के साथ-साथ उनके नशे को कम करने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुश्किल परिस्थितियों में महिलाएं

महिलाओं की स्थितियों की विविधता की पहचान और विशेष रूप से वंचित समूहों की जरूरतों को स्वीकार करने के लिए, उन्हें विशेष सहायता प्रदान करने के लिए उपाय और कार्यक्रम किए जाएंगे। इन समूहों में अत्यधिक गरीबी, निराश्रित महिलाएं, संघर्ष की स्थितियों में महिलाएं, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित महिलाएं, कम विकसित क्षेत्रों की महिलाएं, विकलांग विधवाएं, बुजुर्ग महिलाएं, कठिन परिस्थितियों में अकेली महिलाएं, घरों में रहने वाली महिलाएं, रोजगार से विस्थापित महिलाएं शामिल हैं। प्रवासियों, वैवाहिक हिंसा की शिकार महिलाएं, निर्जन महिलाएं और वेश्याएं आदि।

महिला के विरुद्ध क्रूरता

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी प्रकार, शारीरिक और मानसिक, चाहे वे घरेलू या सामाजिक स्तर पर हों, जिनमें सीमा शुल्क, परंपराओं या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली घटनाओं को प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है। ऐसी हिंसा की रोकथाम के लिए सहायता के लिए संस्थान और तंत्र / योजनाएं बनाई जाएंगी और मजबूत की जाएंगी, जिसमें कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न और दहेज जैसी प्रथाएं शामिल हैं

बालिकाओं के अधिकार

बालिकाओं के प्रति भेदभाव के सभी प्रकार और उनके अधिकारों का उल्लंघन परिवार के भीतर और बाहर निवारक और दंडात्मक दोनों उपायों को मजबूत करके किया जाएगा। ये विशेष रूप से प्रसव पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल शोषण और बाल वेश्यावृत्ति आदि की प्रथाओं को परिवार और बाहर और प्रक्षेपण के भीतर लड़की के इलाज में भेदभाव को दूर करने से संबंधित होंगे। बालिकाओं की एक सकारात्मक छवि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। खाद्य और पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा, और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में बालिकाओं की जरूरतों और पर्याप्त निवेशों को निर्धारित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। बाल श्रम को खत्म करने के कार्यक्रमों को लागू करने में बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संस्थागत तंत्र

महिलाओं की उन्नति के लिए संस्थागत तंत्र, जो केंद्र और राज्य स्तरों पर मौजूद है, को मजबूत किया जाएगा। ये हस्तक्षेप के माध्यम से होगा जैसा कि उपयुक्त हो सकता है और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राप्त करने के लिए मैक्रो-नीतियों, कानून, कार्यक्रमों आदि को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने के लिए पर्याप्त संसाधनों, प्रशिक्षण और वकालत कौशल का प्रावधान, दूसरों के बीच में संबंधित होगा।

राष्ट्रीय और राज्य परिषदें नियमित आधार पर नीति के संचालन की देखरेख के लिए बनाई जाएंगी। राष्ट्रीय परिषद प्रधानमंत्रियों द्वारा प्रधान मंत्री और राज्य परिषदों की अध्यक्षता में होगी और संबंधित विभागों / मंत्रालयों, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों, समाज कल्याण बोर्डों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों की रचना में व्यापक होगी। महिला संगठन, कॉरपोरेट सेक्टर, ट्रेड यूनियन, वित्त पोषण संस्थान, शिक्षाविद, विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता आदि। ये निकाय वर्ष में दो बार नीति को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद को सलाह और टिप्पणियों के लिए समय-समय पर नीति के तहत किए गए कार्यक्रम की प्रगति से भी अवगत कराया जाएगा।

संसाधन प्रबंधन:

नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय, मानव और बाजार संसाधनों की उपलब्धता का प्रबंधन संबंधित विभागों, वित्तीय ऋण संस्थानों और बैंकों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य जुड़े संस्थानों द्वारा किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शामिल होंगे:

(अ) महिलाओं के लिए बहने वाले लाभों का आकलन और लिंग बजट के एक अभ्यास के माध्यम से उनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवंटन। इन योजनाओं के तहत महिलाओं को लाभ का अनुकूलन करने के लिए नीतियों में उचित परिवर्तन किया जाएगा;

(ब) संबंधित विभागों द्वारा उपरोक्त (ए) के आधार पर पहले उल्लिखित नीति को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटन।

(स) स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शिक्षा और महिला और बाल विकास विभाग के कर्मियों के बीच क्षेत्र स्तर और

अन्य ग्राम विकास कार्यकलापों के बीच तालमेल विकसित करना '

(द) महिलाओं और बाल विकास विभाग के समन्वय में उपयुक्त नीतिगत पहलों और नए संस्थानों के विकास के माध्यम से बैंकों और वित्तीय क्रेडिट संस्थानों द्वारा ऋण की जरूरतों को पूरा करना।

नौवीं योजना में अपनाई गई महिला घटक योजना की रणनीति यह सुनिश्चित करना कि सभी मंत्रालयों और विभागों से महिलाओं को 30% से कम लाभ / निधि प्रवाह प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाएगा ताकि महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों और हितों को सभी द्वारा संबोधित किया जा सके संबंधित क्षेत्र। महिला और बाल विकास विभाग नोडल मंत्रालय होने के नाते योजना आयोग के सहयोग से गुणवत्ता और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर घटक योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा।

महिलाओं की उन्नति के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए, निजी क्षेत्र के निवेशों को भी चैनलाइज करने का प्रयास किया जाएगा

विधान

मौजूदा विधायी संरचना की समीक्षा की जाएगी और नीति को लागू करने के लिए पहचान किए गए विभागों द्वारा उठाए गए अतिरिक्त विधायी उपायों की समीक्षा की जाएगी। इसमें सभी मौजूदा कानूनों की समीक्षा भी शामिल होगी, जिसमें व्यक्तिगत, प्रथागत और आदिवासी कानून, अधीनस्थ कानून, संबंधित नियमों के साथ-साथ सभी लैंगिक भेदभावपूर्ण संदर्भों को समाप्त करने के लिए कार्यकारी और प्रशासनिक नियम शामिल हैं। इस प्रक्रिया की योजना 2000-2003 की समयावधि में बनाई जाएगी। आवश्यक विशिष्ट उपाय नागरिक समाज, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए जाएंगे। उपयुक्त मामलों में अन्य हितधारकों को भी शामिल करने के लिए परामर्श प्रक्रिया को चौड़ा किया जाएगा।

नागरिक समाज और समुदाय को शामिल करके कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो कानून में उचित बदलाव किए जाएंगे।

लिंग संवेदीकरण

राज्य के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक विंग के कर्मियों का प्रशिक्षण, नीति और कार्यक्रम के विकास, कार्यान्वयन और विकास एजेंसियों, कानून प्रवर्तन मशीनरी और न्यायपालिका के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अन्य उपायों में शामिल होंगे:

(a) लैंगिक मुद्दों और महिलाओं के मानव अधिकारों के लिए सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

(b) लिंग शिक्षा और मानव अधिकारों के मुद्दों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्रियों की समीक्षा

(c) सभी सार्वजनिक दस्तावेजों और कानूनी उपकरणों से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक सभी संदर्भों को हटाना।

(d) महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण से संबंधित सामाजिक संदेशों को संप्रेषित करने के लिए मास मीडिया के विभिन्न रूपों का उपयोग।

पंचायती राज संस्थाएँ

भारतीय संविधान में) ३ वें और the 4 वें संशोधन (१ ९९ ३) ने महिलाओं के लिए राजनीतिक शक्ति संरचना में समान पहुंच सुनिश्चित करने और भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सफलता के रूप में कार्य किया है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया में पीआरआई एक केंद्रीय भूमिका निभाएगी। पीआरआई और स्थानीय स्वशासन जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

स्वैच्छिक क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी

स्वैच्छिक संगठनों, संघों, महासंघों, ट्रेड यूनियनों, गैर-सरकारी संगठनों, महिला संगठनों और साथ ही शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान से संबंधित संस्थानों की भागीदारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा में सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं को प्रभावित करना। इस अंत तक, उन्हें संसाधनों और क्षमता निर्माण से संबंधित उचित सहायता प्रदान की जाएगी और महिलाओं के सशक्तीकरण की

www.ignited.in

प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

नीति का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तीकरण पर सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों / प्रतिबद्धताओं को लागू करना होगा, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों पर कन्वेंशन (CEDAW), बच्चों के अधिकार पर कन्वेंशन (CRC), जनसंख्या पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और विकास (ICPD + 5) और अन्य ऐसे उपकरण। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग को अनुभवों के आदान-प्रदान, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, संस्थानों और संगठनों के साथ नेटवर्किंग और द्विपक्षीय और बहु-पार्श्व साझेदारी के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।

परिदृश्य के समीक्षा

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि सशक्तीकरण मानव का एक गुण है और एक बहुआयामी घटना है। यह व्यक्तिगत व्यक्तियों या समूहों को भाग लेने और घरों, समुदायों और देशों में राजनीतिक या विकास प्रक्रिया से लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। कई शोधकर्ताओं और निकायों ने बताया है कि सशक्तिकरण कई विकास परिणामों के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। हम इस चर्चा को अनुभाग २.४ में विवरण में रखते हैं। इस सांठगांठ को समझते हुए कई विकासशील देशों जैसे नेपाल, चिली आदि ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट में अभिनव उपायों के साथ सशक्तिकरण पर जोर दिया है। हालांकि, सशक्तीकरण का कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत उपाय नहीं है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि सशक्तिकरण के स्तर को निर्धारित करना मुश्किल है।

निष्कर्ष:

शोध अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ मामलों में, ई-सरकार ने सीमांतों को उनके अधिकारों से दूर करने में हाशिए पर डाल दिया है ।49 सामाजिक समावेशन को अक्सर नीतिगत दस्तावेजों में रखा जाता है, लेकिन महिलाओं के सशक्तीकरण और लैंगिक समानता उनकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट हैं। स्पष्ट नीति दृष्टि और महिलाओं के अधिकारों के लिए संभावित रूप से क्या कर सकती है, इसकी योजना के बिना, ई-सरकार महिलाओं को दरकिनार करने का जोखिम उठाती है। जबकि कोरिया गणराज्य में सरकार 3.0 की हालिया दृष्टि "पारदर्शिता, सक्षमता और नागरिक-उन्मुख सेवाओं" के लिए है, यह 1990 के दशक के अंत में और 2000 के दशक के प्रारंभ में प्रशासन को "एक मुद्दे के रूप में सूचनात्मकता को सक्रिय रूप से समर्थन करने के लिए" का हक है। महिलाओं के मानवाधिकारों "150 को महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखा जा सकता है जिसने ई-सरकार के माध्यम से सकारात्मक लैंगिक समानता परिणामों के लिए कोरिया गणराज्य में मार्ग प्रशस्त किया

प्रतिक्रिया दें संदर्भ:

अफ़रोज़, रहनुमा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय नेटवर्क ऑफ़ वूमेन पार्लियामेंट्रीज़ वूमन पार्लियामेंटरी कॉकस, SARSWP टेक्निकल पेपर 3, सेंटर फॉर जेंडर एंड सोशल ट्रांसफ़ॉर्मेशन, फरवरी 2013।

कैरेन, पैन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (PAHO), 2013 में किशोर, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की स्थिति का विश्लेषण, एलन, कैरोलीन

एंथनी, केनी, ity समानता और न्याय की अवधारणा पर आधारित शासन के लिए एक व्यापक एजेंडा ', OAS मंच पर प्रस्तुति" एक नागरिक लोकतंत्र के लिए महिला नेतृत्व ", 2011।

एंट्रोबस, पैगी, कैरिबियन महिलाओं के आंदोलन में नारीवादी राजनीति का उदय और पतन 1975-1995 (ल्यूसिल मैथुरिन मैयर व्याख्यान), 2000।

एंट्रोबस, पैगी, नारीवादी सक्रियता। 21 वीं शताब्दी में लिंग में कैरिकॉम अनुभव। कैरेबियन परिप्रेक्ष्य, दर्शन और संभावनाएँ, बारबरा बेली और एल्सा लियो-राइनी, संस्करण। किंग्स्टन, इयान रैंडल पब्लिशर्स, 2004।

बैरीटेउ, वायलेट यूडीन, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ़ जेंडर इन द ट्वेंटिएथ सेंचुरी कैरिबियन। हाउंडमिल्स / न्यूयॉर्क, पल्लग्रेव मैकमिलन, 2001।

बैरीट्यू, वायलेट यूडाइन, 'बियॉन्ड बैकलैश: 1990 के दशक में कैरेबियाई महिलाओं के साथ द फ़्रंटल असॉल्ट', कैरेबियन में जेंडर इक्वेलिटी में: रियलिटी या इल्यूजन, गेम्मा टैंग नैन और बारबरा बेली, एड्स, किंग्स्टन, इयान रैंडल। प्रकाशक, 2003।

बैरीट्यू, वायलेट यूडाइन, थेरिज़िंग शिफ्ट फ्रॉम विमेन टू जेंडर, कन्फ़रिंग पॉवर, थेरिज़िंग जेंडर, 2003।

बैरो-गाइल्स, सिंथिया, कैरेबियन पॉलिटिक्स का परिचय: टेक्स्ट और रीडिंग, 2010।

बैरो-गिल्स, सिंथिया, कॉमनवेल्थ कैरेबियन में संवैधानिक विकास में क्षेत्रीय रुझान, एक पत्र जो कि संघर्ष निवारण और शांति मंच के लिए तैयार किया गया था, जनवरी 2010।

बैरो-जाइल्स, सिंथिया, पोलिटिकल पार्टी फाइनेंसिंग और कैरिबियन में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, अध्याय III, http: // www.idea.int/publications/pp_carabeth/upload/ Grass_Chap3.pdf

बैरो-गाइल्स, सिंथिया, महिलाएं, राष्ट्रमंडल कैरिबियन में चुनावी सुधार और राजनीतिक भागीदारी: चुनावी सुधार के माध्यम से परिवर्तन, ओएएस फोरम में "महिला नेतृत्व / लोकतंत्र के लिए महिला नेतृत्व" पर प्रस्तुत पत्र।

बैरो-गाइल्स, सिंथिया, वीमेन इन कैरेबियन पॉलिटिक्स, रैंडल हाउस पब्लिशर्स, जमैका, 2011।

बिलबी, केनेथ एम।, जमैका में मरून स्वायत्तता, सीएसक्यू मुद्दा: 25.4 (शीतकालीन 2001) अमेरिका में मैरून।

बॉटल एस, गुएडेस ए, गुडविन एम, मेंडोजा जेए (2012) लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में महिलाओं के खिलाफ हिंसा: 12 देशों से जनसंख्या आधारित डेटा का तुलनात्मक विश्लेषण। पैन अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन (PAHO), वाशिंगटन, 2012।

बुद्धन, रॉबर्ट। कैरिबियन में राजनीति, विषय तीन: मतदान व्यवहार, व्याख्यान 5-6। http://gtuwi.tripod.com/gt22dlec3। एचटीएमएल

महिला मामलों के ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है, लिंग एजेंडा; गैनिंग मोमेंटस (ब्रोशर), जमैका, 2013।

महिला मामलों के ब्यूरो (लिंग मामले) लिंग सलाहकार समिति, लैंगिक समानता के लिए राष्ट्रीय नीति (NPGE)। किंग्स्टन, जमैका और, अक्टूबर 2010।

कैरेबियन इंस्टीट्यूट फॉर वीमेन इन लीडरशिप (सिविल) और यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन (यूएन वीमेन), जेंडर एंड पोलिटिकल पार्टीज़ इन द कैरेबियन (अभी तक प्रकाशित नहीं)

गुयाना में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि, प्रशिक्षक का मैनुअल: उम्मीदवार कौशल, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्थान (एनडीआई), गुयाना 2004।

इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज (IGDS), पॉलिटिक्स, पावर एंड जेंडर जस्टिस इन द एंजलफोन कैरेबियन, वुमन अंडरस्टैंडिंग

राजनीति, राजनीतिक प्रतियोगिता के अनुभव और लिंग परिवर्तन के लिए संभावनाएँ, सेंट ऑगस्टीन, त्रिनिदाद और टोबैगो।

इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक, गवर्नेंस इन सूरीनाम, IADB पेपर, अप्रैल 2001। • इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO), ILO ब्यूरो फॉर एम्प्लॉयर्स एक्टिविटीज, जेंडर इक्वलिटी पर लीडरशिप ऑर्गनाइजेशन, 10 देशों से केस स्टडी, 2005

अंतर-संसदीय संघ (IPU), संसद का मूल्यांकन, संसदों के लिए एक स्व-मूल्यांकन टूलकिट, 2008।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू), लिंग-संवेदनशील संसदों के लिए कार्य योजना, 2012।

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) और संयुक्त राष्ट्र महिला, 2012 में संसद में महिला, पर्सपेक्टिव में 2013।

ली-जू चेन, क्या लिंग कोटा महिलाओं के प्रतिनिधित्व और नीतियों को प्रभावित करता है? तुलनात्मक अर्थशास्त्र के यूरोपीय जर्नल, वॉल्यूम 7, एन। 1, पीपी। 13-60, आईएसएसएन 1824-2979, 2010।

Corresponding Author

Priti Deshlahara*

Research Scholar, OPJS University, Churu, Rajastan